ग्रामीण अंचलों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजनाएं

296. **श्री कपिल सिब्बल** :

श्री राज मोहिन्दर :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा कतिपय योजनाएं चलाई जा रही हैं,

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के माध्यम से वार्षिक तौर पर रोजगार के कितने अवसर पैदा करने का लक्ष्य हैं,

(ग) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण अंचलों में रोजगार पाने के लिए प्रतिवर्ष योग्य हो रहे नवयुवकों की संख्या का भी आंकलन किया हैं, और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यन्वित योजनाएं तथा 1998-99 के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:-

योजना का नाम	इकाई	1998-99 के लिए लक्ष्य
(1) जवाहर रोजगार योजना	लाख श्रमदिन	3966.57
		(लक्ष्य निर्धारित नहीं)
(2) सुनिश्चित रोजगार योजना		(लक्ष्य निर्धारित नहीं)
(3) दस लाख कुओं की योजना		(लक्ष्य निर्धारित नहीं)
(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम		(लक्ष्य निर्धारित नहीं)
(5) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास (डवाकरा)		50000
(6) ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षणप्रशिक्षणार्थियों की संख्या कार्यक्रम (ट्राइसेम)		288378

(ग) और (घ) 1993-94 में राष्ट्रीय नमूना सवेंक्षण संगठन द्वारा कराए गए अद्यतन पंचवर्षीय सवेंक्षण के अनुसार बेरोजगार ग्रामीण युवाओं की संख्या युजुअल प्रिंसिपल स्टेट्स (यू. पी. एस.) के अनुसार 4.17 मिलियन थी तथा ग्रामीण बेरोजगार लोगों की कुल संख्या 4.71 मिलियन थी । 1987-88 और 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए पिछले दो पंचवर्षीय सवेंक्षणों के परिणामों से स्पष्ट हैं कि यू. पी. एस. के अनुसार ग्रामीण बेरोजगार लोगों की संख्या 1987-88 के 5.27 मिलियन से घटकर 1993-94 में 4.17 मिलियन रह गई । ग्रामीण बेरोजगार लोगों की कुल संख्या 7.17 मिलियन से घटकर सूचित अवधि में 4.71 मिलियन रह गई ।

Amendment of Land Acquisition Act 1894

297. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minsiter of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

Whether Government's attention has been drawn to the news-item in 'The Hindustan Times', dated the 1st January, 1999 under the caption "Proposed amendments of Land Acquisition Act, 1894-Government forced to rethink on rehabilitation aspect" and to state the state the details in this regard?